

## लोकसभा अध्यक्ष अपने “डिस्केशनरी फण्ड” का बहुत “सही” उपयोग कर रहे हैं!

अविश्वास प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए, 60 देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे लोकसभा सचिवालय की ओर से, भारत की संसदीय व्यवस्था की सुंदर कहानी पेश करने के लिए

**-रेणु मि्तल-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 23 फरवरी। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला अपने व्यक्तिगत पीआर के लिए राष्ट्रीय खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च को सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। जब सदन एक ब्रेक के बाद फिर से चलेगा, उसी दिन प्रस्ताव लाया जाएगा। सांसदों और अधिकारियों के बीच गुपचुप चर्चा हो रही है कि स्पीकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी तादाद में नेताओं व सांसदों को 60 देशों में भेजने का कार्यक्रम बनाया है।

विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दौर में किए गए प्रयासों की तरह ही विभिन्न देशों के साथ संपर्क बनाने का

- इस मकसद से 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता ग्रुप बनाए गए हैं।
- विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं, जैसे पी. चिदम्बरम, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश, ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सूले, अनुराग ठाकुर आदि को संसदीय मित्रता ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है।
- श्री लंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, अमेरिका, रूस, यूरोपीयन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान व यू.ए.ई., को भेजे जाने वाले ग्रुप्स गठित हो चुके हैं तथा साथ ही इस सूची में सम्मिलित नाम साठ की संख्या पार कर जाएंगे।
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्र.मंत्री ने भी कई ग्रुप्स बनाये थे, जिन्हें विदेश भेजा गया था तथा इन ग्रुप्स की यात्रा का काफी व्यापक व सकारात्मक असर हुआ था। ओम बिड़ला चाह रहे हैं कि संसदीय ग्रुप की वर्तमान विदेश यात्राओं से भी ऐसा ही नतीजा निकलेगा।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोकसभाध्यक्ष के “डिस्केशनरी फण्ड” का कोई ऑडिट नहीं होता, राष्ट्रपति के “डिस्केशनरी फण्ड” की भांति। अतः संसदीय मंत्री ग्रुप्स की विदेश यात्राएं निर्विज्न रूप से पूर्ण होगी शीघ्र ही।

कार्य करेंगे, ताकि भारत के दृष्टिकोण को सामने लाया जा सके। कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ चल रही आलोचनाओं को दबाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## जल्दी ही अलवर तक भी आएगी रैपिड रेल

दिल्ली से मेरठ तक का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 23 फरवरी। भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), जो दिल्ली से 82 किमी की दूर स्थित मेरठ को जोड़ेगा, अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इस लाइन के अग्रे 26 किमी खंड का उद्घाटन किया। ट्रेनों का परिचालन 10 मिनट के अंतराल पर होगा, जो दिल्ली के समय काले खान से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक की यात्रा 55 मिनट में पूरी करेगी।

साथ ही, मेरठ मेट्रो का 23 किमी का खंड भी लॉन्च किया गया है- जो आरआरटीएस ट्रेकों और सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। अधिकारियों ने कहा, इसे भारत की सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली के रूप में पेश किया गया है, जिसकी अधिकतम संचालन गति 120 किमी/घंटा होगी,

- प्रधानमंत्री ने रविवार को पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विधिवत् उद्घाटन किया।
- इसी बीच केन्द्रीय शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात कही।
- पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुभारंभ के साथ ही मेरठ मेट्रो का 23 किलोमीटर लंबा रेल खंड भी शुरू किया गया। अब देश का मेट्रो रेल नैटवर्क 1100 किलोमीटर तक बढ़ चुका है।

और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी होगी। यात्री चार स्टेशनों पर आरआरटीएस और मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं: मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम।

अधिकारियों ने कहा, अब मेरठ के जुड़ने से, देश का मेट्रो नेटवर्क 24 शहरों में 1,100 किमी तक बढ़ चुका है।

180 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड और 160 किमी/घंटा की संचालन स्पीड के साथ, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस भारत का पहला परिवहन प्रोजेक्ट है, जो क्लस्टर-आधारित शहरी विकास की अवधारणा (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पुनः बिखराव की ओर

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 23 फरवरी। आगामी राज्य सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद

- इस बार मसला है, राज्यसभा की रिक्त हुई सीटों का। महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली होंगी, इनमें से सिर्फ एक विपक्ष को मिलेगी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों घटक, शिव सेना, कांग्रेस व एनसीपी की इस एक सीट पर नजर है।

चुनावों ने विपक्षी खेमें में हलचल मचा दी है और महा विकास अघाड़ी (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश

रांची, 23 फरवरी। रांची से एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रही एक एयर एंबुलेंस सोमवार रात चतरा में क्रैश हो गई। इस विमान पर मरीज समेत कुल सात लोग सवार थे, जिनमें सभी की मौत हो गई।

बताया जाता है कि आग से गंभीर रूप से झुलसे, लातेहार के चंदवा निवासी मरीज संजय कुमार को शाम 7:11 बजे रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के, बीच क्राफ्ट सी 90 एयर एंबुलेंस में

- चतरा जिले के पास सिमरिया में हुए हादसे में विमान में सवार मरीज सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई।

मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी व एक अन्य स्वजन ध्रुव कुमार के अलावा एंबुलेंस टीम के कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराज दीप सिंह, डॉ. विकास कुमार गुप्ता और पैरा मेडिकल स्टाफ सचिन कुमार गुप्ता सवार थे।

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि शाम 7.34 बजे एयर टैफिक कंट्रोल (एटीसी) से विमान का संपर्क अचानक टूट गया। संपर्क टूटते ही तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## हरदीप पुरी के बारे में नया विवाद खड़ा हुआ, एफ्टीन से संबंधों के बारे में

सोशल एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने पुरी का एफ्टीन को लिखा एक पत्र ट्विटर पर डाला

- इस पत्र के अनुसार, पुरी ने एफ्टीन के एक नजदीकी मित्र को 2013 में पत्र लिखकर धन्यवाद दिया, पुरी की पुत्री हिमानी पुरी की व्यवसायिक कंपनी में 2,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। यह उस समय की बात है जब 2013 में, हरदीप पुरी भारत की “फॉरेन सर्विस” की पोस्ट, यू.एन. में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद से रिटायर हुए ही थे तथा उन पर आरोप था कि वे कंपनी से सम्बद्ध बिज़नेस के लिए “लॉबिंग” कर रहे थे।
- इस प्रसंग का एक रोचक पहलू यह भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की बड़ी सुस्त सी प्रतिक्रिया आई। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकरण से जुड़े कागज़ातों की सच्चाई व विश्वसनीयता का गहराई से अध्ययन कर रही है तथा निष्कर्ष पर पहुँचकर ही अपनी प्रतिक्रिया देगी।

कुछ वर्ग इस मामले में स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

विवाद ने तब जोर पकड़ा जब सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे पुरी का निजी पत्र बताया। अपनी पोस्ट में शुक्ला ने आरोप लगाया कि राजनयिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद

पुरी न्यूयॉर्क में अपनी बेटी के कारोबारी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, इस दस्तावेज की प्रामाणिकता और पत्राचार के संदर्भ की अब तक आधिकारिक खोजों से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## असम में कांग्रेस से पलायन रोकना बड़ी चुनौती है प्रियंका के लिए

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेन बोरा ने भाजपा में शामिल होकर प्रियंका के लिए चुनौती बढ़ा दी है

- प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं और उन पर सही प्रत्याशियों के चयन की भी जिम्मेवारी है, साथ ही गठबंधन के लिए सही सहयोगियों की तलाश भी उन्हें करनी है। इसके लिए वे फूक-फूक कर कदम उठा रही हैं।

- अपने हालिया असम दौरे में उन्होंने राज्य के सभी कांग्रेसी विधायकों, सांसदों व जिला तथा ब्लॉक अध्यक्षों से भी मुलाकात की।

- सूत्रों का कहना है कि राज्य में भाजपा का संगठन काफी मजबूत है, कांग्रेस भले ही बड़ी जीत प्राप्त न कर पाए, पर, अगर उसने स्थिति पहले से बेहतर कर ली तो भी इससे प्रियंका की सफलता माना जाएगा।

शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद,

एनडीटीवी से बातचीत में बोरा ने कहा कि वे रविवार को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 8 मार्च

तक कांग्रेस के कई अन्य नेता भी भाजपा में जा सकते हैं।

प्रियंका गांधी के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इस संभावित पलायन को रोकना और चुनाव से पहले पार्टी को

एकजुट रखना होगा।

स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्यों में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डी के शिवकुमार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद इमरान मसूदर शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान, गांधी ने असम के 21 विधायकों, तीन सांसदों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की।

उम्मीदवारों के चयन के अलावा, गांधी और कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती भाजपा का सामना करने के लिए सही सहयोगियों का चयन करना होगा। ज्ञातव्य है कि भाजपा लगातार दो कार्यकाल से सत्ता में है और चुनाव से पहले उसे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 2021 में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 126 में से 75 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोड़ को केवल 50 सीटें मिली थीं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## अनिल अंबानी पर बैंक की कार्यवाही से रोक हटी

मुंबई, 23 फरवरी। उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार झटका लगा। अदालत ने वह स्टे आदेश हटा दिया, जिसने बैंकों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा था। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज की उस अंतरिम राहत को

- बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का स्टे हटाया।

रद्द कर दिया, जिसमें तीन बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक तथा ऑडिटर बीडीओ इंडिया एलएलपी को कार्रवाई से रोका गया था।

यह पूरा मामला आरबीआई की 2024 मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। सिंगल जज ने दिसंबर 2025 में अनिल अंबानी को राहत देते हुए कहा था कि फॉरेसिक ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने वाले (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

विचार बिन्दु

मेरे दोस्त किसी चीज़ को कुरूप ना कहो, सिवाय उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियों से डरने लगे। –खलील जिब्रान

# AI (Artificial Intelligence), AI ( Aam Insaan) के लिये काम आए तो कितना अच्छा हो

17 से 20 फरवरी 2026 के दौरान भारत द्वारा पूरे विश्व की सबसे बड़ी AI summit आयोजित की गई। इसमें कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ ही लगभग 1०0 देशों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विशेषज्ञों ने भाग लिया और इसके विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। इस सफल आयोजन के लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है, इसके बावजूद कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन द्वारा विकसित रोबोट कुत्ते, ओरियन को अपना बताते हुए प्रस्तुत किया, जिससे काफी शर्मिंदा होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किया गया बिना शर्ट के बेहूदा प्रदर्शन भी कोई अच्छा निर्णय नहीं था। इससे विश्व में भारत की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह बात भी सही है कि अब भारत द्वारा एआइ पर अधिक बल दिया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में चीन हमसे बहुत-बहुत आगे निकल चुका है। फिर भी यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर इसे उच्च प्राथमिकता तो दी है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ देश के किस वर्ग को मिलता है? क्या इसका लाभ वही ले पाएंगे जो पहले ही विकास की दौड़ में आगे हैं, सक्षम हैं और समर्थ हैं? यदि ऐसा हुआ तो देश में असमानता, जो पहले ही बहुत अधिक है, और अधिक बढ़ जाएगी। इससे देश में असंतोष बढ़ने की संभावना रहेगी। सरकार को यह समझना होगा कि एआइ तो एक हथियार मात्र है। इसके माध्यम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, यह सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

देश में वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें हमारे देश के वंचित वर्ग की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एआइ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए। पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शोध एवं विकास पर बहुत ही काम धनराशि खर्च की जाती है, जब कि विकसित देश इस पर हमसे कई गुना अधिक खर्च करते हैं। चीन भी इस क्षेत्र में भारत से बहुत अधिक व्यय कर रहा है और यही इस क्षेत्र में उसकी अप्रतिम सफलता का आधार भी है। सातवें दशक के अंत में चीन ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उसका उसे भरपूर मिल रहा है। पूरे विश्व में उसके वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ छाप हुए हैं। एक सर्वे में यह बताया गया कि कुछ वर्षों पूर्व जहां 64 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से 57 में अमेरिका प्रथम स्थान पर था वहीं यह केवल 6 में प्रथम स्थान पर रहा है और 54 में चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। एक प्रकार से तकनीकी विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन ने सभी को पीछे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे बहुत पीछे हो गया है।

अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें इसका उपयोग अब आम ईसान (एआइ) के लिए करने की जरूरत है। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जो हार्शिए पर हैं। इनकी वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा किसी भी गांव में जाने पर अथवा किसी भी शहर की कच्ची बस्ती में कुछ दर रकने से ही लग जाता है। ये वे लोग हैं जिनके बच्चों को या तो शिक्षा नहीं मिलती है या मिलती भी है तो कुछ इस प्रकार की, कि उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। उन्हें जिस सरकारी भवन में बैठकर पढ़ाई करनी होती है, वह कब ध्वस्त हो जाएगा और उनकी जान ले लेगा, इसकी आशंका सदैव बनी रहती है। इन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा का अर्थ ही नहीं है क्योंकि उनके गांव में बिजली कभी कभार ही आती है। इन्हें दूषित पानी पीकर अस्वस्थता की ओर धकेल दिया जाता है। इन्हें अपने गांव में पानी शुद्ध नहीं मिलने के कारण और स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय इन्हीं के जुगाड़ में बिता देना पड़ता है। यदि एआइ उनके लिए कुछ समस्याओं का हल खोज सके और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर सके तो भारत के संदर्भ में यह कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अब तक केवल प्रशासनिक आधार पर उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया गया लेकिन ये सब भ्रष्टाचार की पंज चढ़ने के कारण वास्तव में इन लोगों का कुछ विशेष भला नहीं हो पाया। विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के चलते ही करोड़ों रुपए की सरकारी राशि व्यर्थ चली जाती है, चाहे वह सड़क बनाने के लिए हो, बांध बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, या बांध बनाने के लिए। जब एआइ इतनी तत्कवी कर ही रहा है तो फिर इसका उपयोग करके, क्या हम अपने सिस्टम में से भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते हैं? क्या इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि वास्तव में कौन गरीब है और किसको सरकारी सहायता की आवश्यकता है? क्या एआइ का उपयोग इस काम के लिए नहीं हो सकता कि गरीब बच्चों को लिए जहां शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं वहां पर एआइ के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम प्रभावी रूप से किया जाए।

यदि जवाब देही का काम एआइ के माध्यम से बेहतर तरीके से हो जाए तो न केवल इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी अपितु इससे भ्रष्टाचार पर चोट करने में भी सहायता मिलेगी। एआइ के उपयोग के बाद भ्रष्ट नेता और अफसर की मनमानी पर अंकुश लगने की संभावना बनेगी। बिना किसी विलंब के एआइ के उपयोग से कई समस्याओं का हल निकालना संभव हो जाएगा।

अपराध नियंत्रण में एआइ का बहुत बड़ा उपयोग होने की संभावना है। ऐसा करने पर गरीब लोगों को शोषण से बचाए जा सकेगा और यदि किसी ने ऐसा किया भी तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना अवश्य ही संभव हो जाएगा।

मैं यह सोचता हूँ कि यदि हम एआइ का उपयोग निम्न समस्याओं का हल निकालने में कर सकें तो यह आम ईसानों की प्राप्ति अर्थात देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा:—

एआइ से यह पता लगाना चाहिए कि जो लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं, उनमें से कितनों को इसका लाभ मिला और जिन्हें नहीं मिला उसकी जानकारी तत्काल सबको उपलब्ध हो जाए। जिनके कारण लाभ नहीं मिला उनका विवरण भी तत्काल सार्वजनिक हो जाय तो भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं होगी।

जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनकी सही जानकारी मोहल्लावार, बटन दबाते ही मिल जाए तो संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र में काम करने में सुविधा होगी। जो विद्यार्थी सरकारी योजना के अंतर्गत लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल आदि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन सबको यह सुविधा मिल जाए, इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। एआइ की सहायता से सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों के शैक्षिक स्तर का आंकलन करना संभव है और इसके आधार पर शिक्षकों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति में भी इसके आधार पर एआइ को काम में लिया जा सकता है।

हाल ही में साइबर फ्रॉड के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। क्या इन्हें रोकने में एआइ की मदद नहीं ली जा सकती?

बैंकों से लिए गये ऋण का सदुपयोग हुआ या नहीं यह पता करना सरल है, एआइ और अन्य तकनीकों का उपयोग करके।

श्रमिकों, विद्यार्थियों, कृषकों, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं किंतु यों भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक पात्र तो वंचित रह जाते हैं और तिकड़मबाज लोग, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलकर सरकारी पैसे को चूना लगाने में सफल हो जाते हैं। इनकी पहचान एआइ के माध्यम से करना न केवल संभव, अपितु आवश्यक भी है।

अनेक प्रभावशाली संपन्न लोग, गरीब बनकर, गरीबों के लिए बनी योजनाओं का पैसा हड़प लेते हैं। इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्च की एआइ की सहायता से निगरानी करके। इससे इनकी संपन्नता सामने आ जाएगी।

कई लोग औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती ज़मीन खरीद कर बिना उद्योग लगाए कुछ समय बाद इन्हें ऊंचे दामों में बेचकर गलत रूप से पैसा बना लेते हैं। इसे एआइ की सहायता से रोका जा सकता है, क्योंकि जिओ टैगिंग करके आर्वाइट भूखंड की मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर एआइ के प्रभावी उपयोग से कड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। इससे वास्तविक पात्र शरा प्रतिशत लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। सरकार में पैसे की कमी नहीं, अपितु उसके उपयोग पर कड़ी और सही मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यही काम एआइ की सहायता से बखूबी किया जा सकता है।

आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। इसको कार्यान्वित करने के तो एआइ ने असीमित द्वार खोल दिए हैं।

आशा है, सरकार एआइ समिट की सफलता को “Aam Insaan” (AI) की बेहतरी में काम लेगी। संक्षेप में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग AI यानि “(Aam Insaan)” के लिए करने का समय आ गया है। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाए तो इस समिट की सार्थकता कई गुणा बढ़ जाएगी।

—अतिथि सम्पादक,  
राजेन्द्र भागवत ( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )

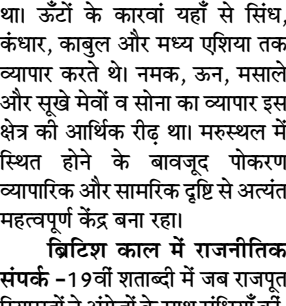
संपादकीय

मरुस्थल की धड़कन : पोकरण

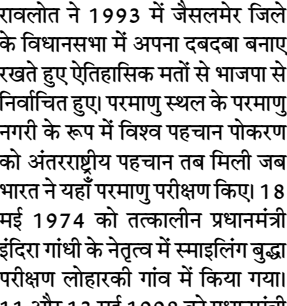
शौर्य, राजनीति और परमाणु शक्ति की ऐतिहासिक नगरी



जुगल किशोर बिस्सा



गुलाब सिंह रावलोट



हड़वत सिंह रावलोट

पश्चिमी राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा पोकरण केवल एक कस्बा नहीं, बल्कि इतिहास, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का जीवंत प्रतीक है। राजपूत शौर्य की गाथाओं से लेकर आधुनिक भारत की परमाणु शक्ति तक, इस मरुस्थलीय नगरी ने हर युग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

**रियासतकाल की गौरवगाथा:**  
**लालकिला और चम्पावत ठिकाना**  
पोकरण की स्थापना लगभग 14वीं शताब्दी (1356 ई.) में मानी जाती है। यहाँ स्थित भव्य पोकरण लालकिला (बालागढ़) आज भी राठौड़ वीरता और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। राजपूत समाज के पोकरणा जाती, मारवाड़ के संस्थापक राव जोधा के वंश से जुड़े चम्पावत राठौड़ यहाँ के ठिकानेदार रहे। पोकरण ठिकाने को मारवाड़ दरबार (जोधपुर) में विशेष सम्मान प्राप्त था और स्थानीय प्रशासन में इसकी निर्णायक भूमिका मानी जाती थी। लाल पत्थर से निर्मित यह किला मरुस्थलीय स्थापत्य की श्रेष्ठ धरोहर है।

**व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र**  
- करियासत काल में पोकरण पश्चिमी व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण पड़ाव था। ऊँटों के कारवां यहाँ से सिंध, कंधार, काबुल और मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। नमक, ऊन, मसाले और सूखे मेवों व सोना का व्यापार इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ था। मरुस्थल में स्थित होने के बावजूद पोकरण व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा।

**ब्रिटिश काल में राजनीतिक संपर्क**  
- 19वीं शताब्दी में जब राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ कीं, तब मारवाड़ राज्य भी ब्रिटिश संरक्षण में आया। पोकरण, मारवाड़ रियासत का

रावलोत ने 1993 में जैसलमेर जिले के विधानसभा में अपना दबदबा बनाए रखते हुए ऐतिहासिक मतों से भाजपा से निर्वाचित हुए। परमाणु स्थल के परमाणु नगरी के रूप में विश्व पहचान पोकरण को अंतरराष्ट्रीय पहचान तब मिली जब भारत ने यहाँ परमाणु परीक्षण किए। 18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण लोहारकी गाँव में किया गया। 11 और 13 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व खेतोलाई गाँव में पाँच सफल परीक्षण किए गए। इन ऐतिहासिक घटनाओं के बाद पोकरण परमाणु नगरी के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित हो गया और भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक बन गया।

**लोकतंत्र की राह: राजनीति का केंद्र**  
- स्वतंत्रता के बाद मारवाड़ रियासत भारतीय संघ में विलय हुई और राजस्थान राज्य के गठन के साथ पोकरण विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। जैसलमेर जिले के गठन के बाद पोकरण क्षेत्र ने लोकतांत्रिक राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमुख ठिकाना होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासनिक ढाँचे से जुड़ा रहा। ठिकानेदारों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच कूटनीतिक संपर्क होते रहे।

रियासतकालीन राजनीति में पोकरण की भूमिका रणनीतिक मानी जाती थी। हिंदुस्तान के पहले लोकतंत्र में इतिहास रचते हुए मेजर रिटायर्ड हड़वत सिंह रावलोट लोहारकी निवासी ने जैसलमेर के पहले 1952 में विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया, वहीं उसी परिवार के गुलाब सिंह

विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर जीव हतिथियों ने हाहाकार मचा दिया। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच बैठी और दो जजों की बैंच के आदेश में संशोधन किया। यह फैसला 11 अगस्त 2025 के उस आदेश को कम नहीं आया, जिसमें सभी कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात कही गई थी, जिसे 22 अगस्त 2025 को संशोधित कर दिया गया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजोरिया की बैंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी जरूरी है, ताकि आवारा कुत्तों को घुसने से रोका जा सके। तीन न्यायाधीशों के इस जजमेंट के बाद डॉग लवर्स और पशु प्रेमी कार्यकर्ताओं को काफी राहत मिली।

जोधपुर निवासी मंजू दहिया ने कहा कि मनुष्य सैकड़ों हजारों वर्षों से अन्य जीवों के साथ प्रेम पूर्वक रहता आया है। प्रकृति ने सबको जीने का समान अधिकार दिया है। अगर मनुष्य खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने तथा अन्य जीवों को धरती का बोझ समझने की भूल करेगा तो ईश्वर कोरोगा जैसी आपदा से मनुष्य को सजा देने में भी देरी नहीं करेगा। मनुष्य को ऊपर वाले के जजमेंट से थोड़ा डरना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी सनातनी परंपरा में घर की माताएं पहली रोटी गाय के लिए तथा दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालती है। दुनिया की किसी कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि गाय कुत्तों के लिए प्रथम रोटी देने वाली मां को जेल भेजने की बात करें। उन्होंने कहा कि मूक पशु बोल नहीं सकते, इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें ईसाफ नहीं चाहिए।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय संस्कृति में सब जीवों को बराबर का दर्जा दिया गया है। संत नामदेव और कुत्ते का प्रसंग आज दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। महान संत नामदेव एक दिन भोजन बना रहे थे। उन्होंने रोटी बनाई और सोचा कि संकल्पनाओं में कुत्तों को सीधे भोग लगा लूं। उन्होंने रोटी बनाकर रखी ही थी कि एक कुत्ता अचानक से उनकी कुटिया में आया और रोटी लेकर भाग गया। संत नामदेव ने देखा तो विचार किया कि मैंने रोटी पर घी तो लगाया ही नहीं।

उनकी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और सर्वव्यापी दृष्टि थी। कुत्ता नामदेव की रोटियां लेकर भागा, तो वे हाथ में घी का कटोरा लेकर पीछे लड़े। बोले, "रोटी रखी है, मख खाओ" कहते-कहते कुत्ते के पीछे दौड़ते रहे। कुत्ता आगे-आगे और संत नामदेव पीछे-पीछे भागने लगे। हाथ में कटोरा लिए संत नामदेव से तेजी से नहीं भागा

जा रहा था। इसलिए वे जोर-जोर से आवाज भी लगाते रहे कि 'प्रभु, रोटी पर घी तो लगाने दो।'

दरअसल संत नामदेव हर जीव में भगवान का दर्शन करते थे। उन्हें उस कुत्ते में भगवान नजर आ रहे थे। रोटी में घी लगाकर खिलाना चाहते थे, ताकि प्रभु को रूखी रोटी न खानी पड़े। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में अन्य जीवों में भगवान का स्वरूप देखने की परम्परा रही है।

हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव (शिव के उग्र रूप) का वाहन माना गया है, जो सुरक्षा, निष्ठा और सतर्कता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ कथाओं में कुत्ते को यमदूत का सहचर और मृत्यु के बाद आत्माओं का मार्गदर्शक भी माना गया है। कुछ लोकमान्यताओं में कुत्तों को सीधे भैरव बाबा का अवतार भी माना जाता है। संक्षेप में, कुत्ता हिंदू धर्म में एक पवित्र प्राणी है, जो सुरक्षा, निष्ठा और संरक्षण का प्रतीक है।

कुत्ते को लेकर एक अन्य प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत के अंत के बाद पाण्डव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े थे। द्रौपदीनाथ के बाद जब पाण्डव हिमालय की पहाड़ियों में आगे बढ़ने लगे तो एक कुत्ता उनके साथ-साथ चल पड़ता है। मार्ग में द्रौपदी, सदेव, नकुल, अर्जुन और भीम की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर पर दुखों का पहलू टूट पड़ता है। कुत्ता भी उनके दुख में

सहभागी बना रहा। कुछ विश्राम के बाद युधिष्ठिर स्वर्गारोहण यात्रा पर आगे के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वह कुत्ता भी उनके साथ रवाना हो गया। दोनों चलते चलते सतोपंथ तीर्थ पहुंचे। वहां स्नान के बाद जब युधिष्ठिर कुत्ते के साथ यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो भगवान इंद्र अपने रथ के साथ उन्हे लेने आए। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ते को देखा तो इंद्र ने कुत्ते को स्वर्ग में ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुत्ते के साथ स्वर्ग प्रवेश वर्जित है। उस कुत्ते को यहीं छोड़ना पड़ेगा।

इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा कि जिसने अंतिम समय में मेरा साथ दिया, वफादारी निभाई, उसे अंतिम क्षण में नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, "स्वर्ग का सुख इस वफादार साथी को छोड़ने के दुख के आगे कुछ भी नहीं है।"

धर्मराज युधिष्ठिर की जीव के प्रति करुणा देखकर भगवान इंद्र प्रसन्न हो उठे। इतने में कुत्ते के रूप में मौजूद धर्मदेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रुप धारण किया था। हिन्दू धर्म के ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें कुत्ते तथा गाय को 'आवारा' नहीं बल्कि, "पूज्यनीय" बताया गया है।

—मिश्रीलाल पंवार,  
( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार है )



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।



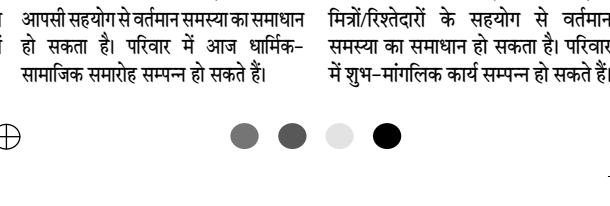
सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।





# कांग्रेस विधायक दल की बैठक में धारीवाल और डोटासरा के बीच हुई तीखी बहस

डोटासरा द्वारा बैठक में बोलने का अवसर न दिए जाने से नाराज होकर शांति धारीवाल बैठक छोड़कर चले गए और बाद में सदन में भी उपस्थित नहीं रहे

**-विधानसभा संवाददाता-**  
जयपुर। राजस्थान विधानसभा की “ना पक्ष” लॉबी में सोमवार सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस के अधिकांश विधायक शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और चर्चा में भाग लिया। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच बहस भी हुई। डोटासरा द्वारा बोलने का अवसर न दिए जाने से नाराज धारीवाल बैठक छोड़कर चले गए

■ बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी

और बाद में सदन में भी उपस्थित नहीं रहे।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के शेष सत्र में सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने की रणनीति तैयार करना था। हाल के दिनों में सदन में 2 साल बनाम 5 साल के

मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस और हंगामा हुआ था। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रतिवेदन पेश किया और कांग्रेस के 5 साल के शासन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने बैठक

में तय किया कि वह सदन में आक्रामक रुख अपनाएगी और सरकार की कमियों को उजागर करेगी। रणनीति के तहत कांग्रेस ने कई प्रमुख मुद्दों पर फोकस करने का फैसला किया। इनमें बंदरों के आतंक से किसानों-नागरिकों की परेशानी, पेंशन संबंधी शिकायतें, महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्जमाफी की प्रगति, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की खामियां शामिल हैं। कांग्रेस विधायक दल ने तीन विभागों की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सरकार से सवालों की बाँछार करने की योजना बनाई। साथ ही,

प्रश्नकाल में विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और याचिकाओं के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने पर जोर दिया गया। जूली ने बैठक के बाद संकेत दिए कि कांग्रेस अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि ठोस विकल्प पेश करेगी। मुख्य सचेतक रफीक खान ने बताया कि विधायकों में एकजुटता दिखी और सभी ने सरकार की घोषणाओं पर आधारित राजनीति की आलोचना की। बैठक में यह भी तय हुआ कि सत्र के दौरान हंगामे से बचते हुए जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार दबाव बनाया जाएगा।

## बीकानेर में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या को लेकर सदन में हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

गृह राज्यमंत्री ने सदन में कहा “पुलिस जांच जारी है, जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे”

**-विधानसभा संवाददाता-**  
जयपुर । राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान बीकानेर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ। आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक हूंराम गेदर ने बीकानेर की घटना को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि मामले में पुलिस जांच जारी है। नाबालिग का शव मोचरी में रखा गया है और बीकानेर के पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

■ परंतु नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि “प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आने के बावजूद सरकार अपराध नियंत्रण पर गंभीरता से काम नहीं कर रही।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि

यदि सरकार अपराध नियंत्रण पर गंभीरता से काम करती तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने नेता प्रतिपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। जवाब में बेदम ने कहा कि एक गंभीर अपराध के मामले में भी राजनीति करना उचित नहीं है और इसे ओछी राजनीति बताया। इस पर टीकाराम जूली ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में पूछना राजनीति नहीं है। इससे पहले, विधानसभा में इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई।

## 44 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला तस्कर के कब्जे से 44 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है।

## ‘विपक्ष के पास ना खुद की उपलब्धियां और ना ही कोई मुद्दा, इसलिए कर रहे है हंगामा’

जयपुर ( विसं )। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने विधानसभा में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सरकार के सवा दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सदन में दिए गए वक्तव्य ने राज्य की राजनीति में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि जो कार्य पूर्ववर्ती सरकार अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वे कार्य वर्तमान सरकार ने अल्प

समय में पूर्ण कर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस दल में हलचल तेज हो गई है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में आंतरिक असंतोष भी देखा गया है। यह भी सामने आया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी सदन में भूमिका को लेकर सवाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने यह भी पूछा कि यदि पूर्व

सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए थे, तो उन्हें सदन में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। इसी संदर्भ में हाल के दिनों में पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक मतभेदों की चर्चाएँ भी तेज हुई हैं, बताया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में हुई बैठकों के दौरान प्रदेश नेतृत्व को विधानसभा में अपेक्षित प्रदर्शन न करने को लेकर भी फटकार मिली। विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया गया कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर

प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रखा गया। इस दौरान हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए व ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उपचुनावों में विकास के दम पर हमें विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती है काम नहीं करती। कांग्रेस सदन में चर्चा में भाग नहीं ले रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस दलित विरोधी है तथा दलित नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

## धौलपुर में सैचुरी से रास्तें बंद

जयपुर ( विसं )। कांग्रेस विधायक संजय जाटव ने धौलपुर जिले में सैचुरी क्षेत्रों के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चिन विभाग ने गांवों के रास्ते बंद कर दिए हैं और फोर्स तैनात कर दी गई हैं। जाटव ने कहा कि जिन गांवों को उनके पूर्वजों ने सदियों पहले बसाया, आज वहां के लोगों को घुट-घुटकर जीना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं के फैसलों को नहीं माना जा रहा और परंपरागत नैन भूमि से लोगों को बेदखल किया जा रहा है।

## जयपुर को मिली ब्रिक्स बैठक की मेजबानी

मुख्य सचिव ने की ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की तैयारियों पर चर्चा

**जयपुर (कासं)।** जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में सोमवार को समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलों विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर में इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य का बात है। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समग्रबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यक्रमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार को उच्चाधिकारियों की बैठक ली।

प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के लिए सुचारु परिवहन व्यवस्था, पायलट वाहन तथा आवश्यकतानुसार रूट क्लियरेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों एवं भ्रमण मार्गों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और

खरखाब सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विधायकों के तहत 24 घंटे चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा नजदीकी अस्पतालों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा

करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा को झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रतिनिधियों के लिए राज्य की कला

एवं हस्तशिल्प से जुड़े स्मृति-चिह्न तैयार करने तथा पर्यटन पुस्तिका की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय के लिए लयजान अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में आर्थिक मामलों विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथई, संयुक्त सचिव अमित सिंगला और निदेशक प्रकाश राजपुरोहित सहित जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं सांस्कृतिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री ए. राठौड़, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव गरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पट्टी, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस), पुलिस आयुक्त जयपुर, विभिन्न विभागों के शासन सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें : भजनलाल शर्मा

8 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित 6 पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली।

**जयपुर ( कासं )।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बचाना भी विद्युत उत्पादन के समान है। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर सघन दौरें कर बिजली चोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स सस्ते होने के साथ ही लम्बी अवधि के लिए कारगर हैं, जिससे आने वाले समय में पर्याप्त बिजली मिलना संभव हो सकेगा। इससे किसानों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ता को भी गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए, ताकि इनका लाभ उपभोक्ताओं को शीघ्र मिल सके।

■ किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता : सीएम

उन्होंने प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करने एवं कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय कार्यालयों पर जल्द से जल्द सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों में अब तक सोलर पैनल नहीं लगे हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। बैठक में 8 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित 6 प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

## डॉ. सतीश पूनियां ने भेंट की पुस्तक



जयपुर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने राजस्थान विधानसभा पहुंचकर “अग्निपथ नहीं जनपथ” पुस्तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, मंजू बाधमार, हेमंत मीणा, विधायक उदयलाल भडाना, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, आदुराम मेघवाल, हमीर सिंह भायल, चंद्रभान आह्व्या, ऋतु बादराव, रामविलास मीणा, अनीता भदेल, दीप्ति माहेश्वरी, पब्ब्याराम विश्नोई, छगन राजपुरोहित तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेंट की।

## “ 2 साल बनाम 5 साल ’’ पर सियासी बयानबाजी तेज

राजेन्द्र राठौड़ ने गहलोत को दी खुली बहस की चुनौती

**जयपुर ( कासं )।** राजस्थान में दो साल बनाम पांच साल को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। राठौड़ ने गहलोत के बयान को “उल्टा बांस बेली” वाली कहावत बताया। राठौड़ ने कहा कि 21 फरवरी को विधानसभा में वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा निर्धारित थी। यह बहस प्रदेश की जनता के सामने दोनों कार्यकालों की उपलब्धियों और नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण रखने का अवसर था, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने सुनियोजित तरीके से हंगामा कर चर्चा से किनारा कर लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अपने 5 साल के कार्यकाल का

ठोस रीपोर्ट कार्ड नहीं था, इसलिए बहस से बचने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री स्वयं सदन में उपस्थित थे और विपक्ष के हर प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर देने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने सदन में अपनी बात रखने के बजाय बाहर बयानबाजी का रास्ता चुना। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में अपराध और महिला अत्याचार के मामलों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के दो वर्षों में कुल अपराधों में लगभग 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उनके अनुसार, हत्याओं में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों में 28 प्रतिशत,

डकैती में 47 प्रतिशत और लुटपाट में 51 प्रतिशत की कमी आई है। राठौड़ ने विकास कार्यों को लेकर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं और योजनाओं का श्रेय गहलोत ले रहे हैं, वे धरातल पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में साकार हुई हैं।

उन्होंने गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि कानून-व्यवस्था, विकास या शासन के किसी भी पहलू को लेकर कोई शंका है तो सदन में खुली और तथ्याधारित बहस की जाए। जनता सब देख रही है और तथ्यों के आधार पर निर्णय करना जानती है। राठौड़ के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं। दो साल बनाम पांच साल का मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा कर सकता है।

## भट्टा बस्ती में चाकू मारकर किशोर की हत्या, दो आरोपी हिरासत में

जयपुर। भट्टा बस्ती इलाके में मामूली कहासुनी के बाद युवक (किशोर) की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार घटना भोमियाजी की बस्ती की है। यहां रहने वाले आदिल का आसपास के कुछ युवकों से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी झगड़े में बदल गई और आरोपियों ने आदिल पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आदिल को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर) बजरंग सिंह

शेखावत ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर समीर,अरबाज सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी और विवाद हो चुका था। रविवार रात मामूली बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और कुछ लोग भट्टा बस्ती थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी का मांग को लेकर थाने का बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है।





